

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 मई, 2021, डिस्पेंच दिनांक 1 मई, 2021

| वर्ष 64 | अंक 23 | भोपाल | 1 मई, 2021 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

प्रदेश में लघु, कुटीर और मध्यम उद्योगों का जाल बिछाना मेरा सपना भी और संकल्प भी : मुख्यमंत्री

एक साल में 12 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य • मध्यप्रदेश के 1891 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का वर्चुअल शुभारंभ

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में लघु, कुटीर और मध्यम उद्योगों का जाल बिछे यह मेरा सपना भी है और संकल्प भी। इस स्तर के उद्योग ही रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराते हैं। रोजगार आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण का मूल आधार है। राज्य शासन उद्यमियों की मदद के लिए सदैव तत्पर है। इस दिशा में आरंभ की गई "स्टार्ट यूअर बिजनेस इन थर्टी डेज" योजना का उद्देश्य यही है कि प्रदेश में अपना उद्योग आरंभ करने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी न आए। हमारा यह लक्ष्य है कि हर महीने प्रदेश के एक लाख लोगों को रोजगार दिलाया जाए। इस प्रकार एक साल में बारह लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में हम निरंतर सक्रिय हैं। लोगों के लिए रोजगार सृजन में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग राज्य सरकार के सहयोगी ही हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान मिंटो हॉल में मिशन अर्थ के अंतर्गत प्रदेश के 1891 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के वर्चुअल शुभारंभ के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

खरगोन के नवीन कलेक्ट्रेट भवन का शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में खरगोन के नवीन कलेक्ट्रेट भवन का वर्चुअल शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि खरगोन में विभिन्न शासकीय कार्यालय अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग भवनों में लगते थे। नवीन कलेक्ट्रेट बनने से सभी कार्यालय एक भवन में लगेंगे। यह जनता के लिए सुविधाजनक होगा। कार्यक्रम में किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सकलेचा उपस्थित थे। खजुराहो सांसद तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री व्ही.डी. शर्मा वर्चुअली सम्मिलित हुए।



अधोसंरचना निर्माण, कृषि और खाद्य प्र-संस्करण में उद्यमशीलता और रोजगार की अपार संभावनाएँ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना के कठिन काल में आत्म-निर्भर भारत के निर्माण का मंत्र दिया। इसके परिपालन में आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए विकसित रोडमैप में

अर्थ-व्यवस्था और रोजगार प्रमुख आधार स्तंभ हैं। प्रदेश में अधोसंरचना निर्माण, कृषि और खाद्य प्र-संस्करण में उद्यमशीलता और रोजगार के अवसर सुजित करने की अपार संभावनाएँ हैं। कोरोना के कठिन काल में प्रदेश के पथ विक्रेताओं और स्व-सहायता समूहों को राज्य शासन द्वारा हरसंभव सहयोग प्रदान किया गया है।

प्रदेश के युवा नौकरी माँगने वाले नहीं रोजगार देने वाले बने
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि युवाओं के लिए स्व-रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से पुरानी योजनाओं की रीपेकेजिंग कर नई मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के विकास के लिए जितना योगदान बड़े उद्योगों का है उतनी ही

महत्वपूर्ण भूमिका एम.एस.एम.ई की है। इसकी महत्ता को स्वीकार करते हुए ही प्रदेश में पृथक एम. एस.एम.ई. विभाग बनाया गया। मेरा सपना है कि प्रदेश के युवा नौकरी माँगने वाले नहीं रोजगार देने वाले बने। यह सपना लघु, कुटीर और मध्यम उद्योगों से ही साकार हो सकता है।

कोरोना से बीमार न होना ही प्रदेश की सबसे बड़ी सेवा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सभी उद्यमियों से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना से बीमार न होना ही प्रदेश की सबसे बड़ी सेवा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए आत्म-अनुशासन अपनाते हुए मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग, बार-बार हाथ धोने की गाइडलाइन का आवश्यक रूप से पालन करें और अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रति भी सतर्क, सावधान और जिम्मेदार रहें।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

पहली बार, एनसीडीसी को डॉएच बैंक ए.जी. से 68.87 मिलियन यूरो ऋण की प्राप्ति



परिदृश्य और जर्मनी के साथ अपने आर्थिक संबंधों को एक नई दृष्टि दी है। उन्होंने कहा कि देश में स्थापित किए जा रहे किसान उत्पादक संगठन आईसीसी और डॉएच बैंक के साथ एनसीडीसी समझौतों के माध्यम से आसान ऋण और बाजार तक पहुंच बना सकेंगे।

यह पहली बार है कि दुनिया के सबसे बड़े यूरोपीय बैंकों में से यह बैंक एनसीडीसी को ऋण प्रदान कर रहा है, इस प्रकार भारतीय विकास वित्त संस्थान में वैश्विक वित्तीय संस्थान के आत्मविश्वास को दर्शाता है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब कोविड-19 संकट द्वारा उत्पन्न

वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल ने ऋण को एक चुनौतीपूर्ण कथन बना दिया है।

डॉएच बैंक एजी के सीईओ और देश प्रमुख, कौशिक शपारिया ने एक बयान में कहा कि वह एनसीडीसी के साथ कृषि क्षेत्र में मजबूत संबंधों की उम्मीद कर रहे हैं।

इस दौरान एनसीडीसी के प्रबंध निदेशक संदीप नायक ने कहा कि किसानों को स्थायी, जलवायु-अनुकूल कृषि की दिशा में एक सफल केंद्र बिंदु बनाने में वित्त एनसीडीसी की मदद करेगा। प्रबंध निदेशक ने कहा कि "सहकारी संस्थाओं के लिए 1963 से एक संगठन के रूप में हमारी स्थापना के बाद, हम हमेशा

(शेष पृष्ठ 6 पर)

भोपाल रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म नं. 6 पर 300 बिस्तर का कोविड केयर सेंटर शुरू

चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सारंग ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया

भोपाल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने आज भोपाल रेल्वे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर 20 आइसोलेशन कोच में बनाये गए लगभग 300 बिस्तर वाले कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। रेल मंडल द्वारा तैयार किये कोविड केयर सेंटर को आज से शुरू किया गया है। तैयार किये गए आइसोलेशन कोच में एसिम्टोमैटिक कोविड मरीजों को रखा जाएगा। ऐसे मरीज जिनके घरों में बुजुर्ग, गर्भवती महिला, बच्चे होने पर परेशानी हो रही है। साथ ही ऐसे पॉजिटिव मरीज जो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं लेकिन उनके घरों में जगह नहीं है और उनको आवश्यकता है कि वह डॉक्टर की निगरानी में रखे जायें। ऐसे मरीज इस सेंटर में आकर अपना बेहतर तरीके से इलाज करा सकते हैं और आइसोलेशन में रह सकते हैं।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सारंग ने निरीक्षण के दौरान बताया कि इस सेंटर पर प्रतिदिन मनोचिकित्सक भी निरीक्षण करेंगे और लोगों को बेहतर तरीके से इस बीमारी से सामना करने के संबंध में बताएंगे। इसके साथ ही



यहाँ पर प्रतिदिन डॉक्टरों की टीम अपने आधुनिक संसाधनों के साथ 24x7 उपस्थित रहेंगी।

रेल मंडल की सराहनीय पहल द्वारा यह सेंटर शुरू किया गया है। इनमें 300 बिस्तर संपूर्ण वेंटिलेशन के साथ तैयार किये गए हैं, जिनमें 300 लोगों को रखा जा सकेगा। सभी कोच में बेहतर व्यवस्थाएँ, खुली हवा आने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्थाएँ की गई हैं। यहाँ प्रतिदिन योगा कराने, स्वास्थ्य वर्धक खाना, दवाइयों

और डॉक्टरों की टीम विजित करेगी।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सारंग ने बताया कि प्रत्येक जिले में एसिम्टोमैटिक मरीजों के लिए कोविड सेंटर चालू कर दिए गए हैं। ऐसे मरीजों में जो बिना लक्षण के भी पॉजिटिव पाए जाते हैं उन सभी लोगों के लिए एक बेहतर इंतजाम होगा। इसके साथ ही डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी भी करती रहेगी और यदि किसी मरीज की स्थिति

थोड़ी भी बिगड़ती है तो उन्हें तुरंत ही डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाएगा। निरंतर इनका ऑक्सीजन लेवल भी चेक किया जाएगा और आवश्यकता होने पर उनको तुरंत विशेष उपचार भी दिए जाने की सुविधा इन सेंटरों में रखी गई है।

मोतीलाल स्टेडियम में 500 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर शीघ्र प्रारंभ होगा
चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है

कि शीघ्र ही मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में 500 बिस्तर का कोविड केयर सेंटर प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, गुजराती समाज, ब्राह्मण समाज सहित अन्य समाज योगदान दे रहे हैं। इस कोविड सेंटर को शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा और यहाँ सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कराई जाएगी।

श्री सारंग ने कहा कि इस कोविड सेंटर के प्रारंभ होने से विभिन्न अस्पतालों में आ रहे कोविड मरीजों के उपचार में राहत मिलेगी, साथ ही कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों पर कोविड मरीजों के भर्ती होने का दबाव कम होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे एसिम्टोमैटिक मरीज तथा बिना लक्षण वाले मरीजों को भी यहाँ संपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएगी।

श्री सारंग ने कहा कि बेहतर उपचार और स्वास्थ्य सुविधा प्रदेश की जनता को उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है और इस दिशा में सतत कार्य तथा निगरानी की जा रही है।

इंदौर संभाग में जल जीवन मिशन में हो रहे 1999 करोड़ रु. के कार्य

भोपाल। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण आबादी को शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था किए जाने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयास तेजी से जारी हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा इंदौर संभाग में 1861 जल प्रदाय योजनाओं का कार्य जारी है। इन जलप्रदाय योजनाओं की लागत 1998 करोड़ 84 लाख 72 हजार रुपये है। विभाग के मैदानी कार्यालयों द्वारा जल जीवन मिशन के मापदण्डों के अनुसार कार्य प्रारंभ कर दिये गए हैं।

प्रदेश की समग्र ग्रामीण आबादी को घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल की आपूर्ति किए जाने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जलसंरचनाओं की स्थापना एवं विस्तार के कार्य किए जा रहे हैं। इनमें इन्दौर जिले की 387, झाबुआ 180, धार 351, अलीराजपुर 114, बड़वानी 258, खण्डवा 256, खरगोन 232 तथा बुरहानपुर की 83 जलसंरचनायें शामिल हैं। इन जिलों के विभिन्न

ग्रामों में पूर्व से निर्मित पेयजल अधोसंरचनाओं को नये सिरे से तैयार कर रेट्रोफिटिंग के अन्तर्गत भी कार्य किये जा रहा है।

इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश जल निगम भी इंदौर संभाग के 91 ग्रामों में नल कनेक्शन के जरिये जल उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है। धार तथा खण्डवा जिलों के इन ग्रामों में 30 हजार 972 नल कनेक्शन दिए जायेंगे। इन जलप्रदाय योजनाओं के पूर्ण होने पर एक लाख 89 हजार से अधिक ग्रामीण आबादी को लाभ पहुँचेगा।

इन जलप्रदाय योजनाओं में जहाँ जलस्रोत हैं, वहाँ उनका समुचित उपयोग कर आसपास के ग्रामीण रहवासियों को पेयजल प्रदाय किया जायेगा। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में जलस्रोत नहीं हैं वहाँ जलस्रोत निर्मित किए जायेंगे। समूची ग्रामीण आबादी के लिए यह व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से दिसम्बर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये सरकारी प्रयासों के साथ जन-सहयोग जरूरी



भोपाल। जन जातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये सरकारी प्रयासों के साथ-साथ जन-सहयोग जरूरी है। उन्होंने स्वयंसेवी संगठनों से वैश्विक महामारी से निपटने के लिये एक जुट होकर कार्य किये जाने का आग्रह भी किया। जन जातीय कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह गुरुवार को उमरिया में जिला संकट प्रबंधन समिति की बैठक को संबोधित कर रही थीं।

जन जातीय कार्य मंत्री सुश्री

मीना सिंह ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने, प्रायवेट अस्पतालों में बिस्तर आरक्षित कराने और दवाओं की दरें निर्धारित करने का कार्य प्राथमिकता के साथ कर रही है। इन सब के बावजूद संकट की इस घड़ी में स्वयंसेवी संगठनों को आगे आकर जन-सामान्य के बीच जन-जागरूकता का काम किये जाने की जरूरत है। उन्होंने आमजन से मास्क पहनने, दो गज

की दूरी का पालन करने और थोड़ी-थोड़ी देर में साबुन से हाथ धोने का आग्रह किया।

जन जातीय कार्य मंत्री ने बताया कि जिले भर में पर्याप्त संख्या में टीकाकरण केन्द्र बनाये गये हैं। उन्होंने 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों से निःशुल्क टीके लगवाने का भी आग्रह किया। कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव ने बैठक में जिला प्रशासन द्वारा किये जा रहे कार्यों और तैयारियों की जानकारी दी।

कोरोना के विरुद्ध युद्ध में मुख्यमंत्री से लेकर पंच तक एक हों : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कोरोना प्रबंधन पर ग्रामीण क्षेत्रों के जन-प्रतिनिधियों से चर्चा की

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना के विरुद्ध युद्ध में मुख्यमंत्री से लेकर पंच तक एक हो जायें तो कोरोना को पराजित किया जा सकता है। यदि हमने हमारा गाँव बचा लिया, तो हम प्रदेश और देश को बचाने में भी सफल हो जाएंगे। कोरोना का संकट बड़ा है पर हमारा हौसला उससे भी ज्यादा बड़ा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान निवास से ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीण निकायों के जन-प्रतिनिधियों से कोरोना प्रबंधन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर रहे थे।

14 हजार 700 पंचायतों ने स्व-प्रेरणा से लगाया जनता कर्फ्यू

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना के विरुद्ध यह लड़ाई योजनाबद्ध तरीके से लड़ी जाएगी। इसकी रणनीति के अंतर्गत दो स्तरों पर कार्य करना है। प्रथम जो संक्रमित हो गए हैं उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित हो और दूसरा संक्रमण की चेन टूटे। कोरोना रूपा राक्षस अपनी शक्ति भीड़-भाड़ से पाता है। अतः संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए भीड़ की संभावनाओं को



शून्य करना होगा। जो शादी, विवाह टाले जा सकते हैं, उन्हें अपने और देश के हित में टालें। हम प्रण लें कि भीड़ इकट्ठी नहीं होने देंगे। प्रदेश की 14 हजार 700 पंचायतों ने स्व-प्रेरणा से जनता कर्फ्यू लगाया है। गाँव वाले स्वयं कोरोना कर्फ्यू का क्रियान्वयन कर रहे हैं। पिछले दिनों प्रभावी रहे इस प्रयास से कई जिलों का पॉजिटिविटी रेट घटा है।

प्रतिदिन 9 से 10 हजार व्यक्ति हो रहे हैं स्वस्थ
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा

कि जो व्यक्ति कोरोना से प्रभावित हैं, उनके इलाज की घर पर ही व्यवस्था के लिए होम आयसोलेशन के अंतर्गत डॉक्टरी सलाह और सावधानियों की जानकारी देने की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग के लिए योग प्रशिक्षकों को भी जोड़ा जा रहा है। जिन लोगों के घरों में आयसोलेशन की व्यवस्था नहीं है, ऐसे मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर में व्यवस्था की गई है। जिन गाँवों में सर्दी, खाँसी, जुकाम ज्यादा लोगों को है या कोरोना के संभावित व्यक्ति हैं, वहाँ पंच,



ग्रामीण भाइयों, मजदूरों, किसानों का हरसंभव ध्यान रखा जा रहा है। तीन महीने का निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेण्डर्स के खाते में एक-एक हजार रूपए डाले जा रहे हैं। प्रदेश में एक मई से 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। ग्राम स्तर पर अधिक से अधिक व्यक्तियों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

होम आयसोलेशन पर नजर रखें स्व-सहायता समूह

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्व-सहायता समूहों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोरोना संक्रमण के विरुद्ध जागरूकता और संक्रमण की चेन तोड़ने और होम आयसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों की देखभाल में यह समूह सहयोगी रहते हुए सक्रिय रहेंगे। ग्राम स्तर पर साफ-सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सहयोग, समन्वय और सद्भाव से ही कोरोना के विरुद्ध विजय प्राप्त होगी।

सरपंच, आशा कार्यकर्ता, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक मिलकर घर-घर सर्वे करें और हर बीमार व्यक्ति को मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाए। छिंदवाड़ा, खण्डवा, बुरहानपुर में इस दिशा में हुए कार्य से संक्रमण की दर को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। प्रदेश में अब प्रतिदिन 9 से 10 हजार व्यक्ति स्वस्थ हो रहे हैं।

टीकाकरण को करें प्रोत्साहित

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना के कठिन काल में

प्रदेश में 291 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भारत सरकार द्वारा 726 करोड़ रु. स्वीकृत

लोक निर्माण मंत्री श्री भार्गव ने आभार ज्ञापित किया

भोपाल। लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने प्रदेश में 14 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की 291 किलोमीटर सड़कों के निर्माण व सुदृढीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा 726 करोड़ रूपए की स्वीकृति प्रदान किए जाने पर, केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी के प्रति आभार ज्ञापित किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से विकास को नई गति मिल सकेगी।

प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्री नीरज मंडलोई ने बताया कि भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश में 14 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के तहत नवीन मार्गों की डीपीआर तैयार करने, पूर्व से स्थापित राष्ट्रीय राजमार्गों के सुदृढीकरण तथा नवीन मार्गों के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रमुख सचिव ने बताया कि एनएच 30 पर सोहागी, गढ़ और कटरा कस्बे में सड़क मार्गों के

सुदृढीकरण के लिए 7 करोड़ 83 लाख रूपए स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार 572 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए 21 करोड़ 87 लाख रूपए, गुलगंज से अमानगंज एनएच 43 के सुदृढीकरण के लिए 7 करोड़ 45 लाख रूपए, सागर से छतरपुर एनएच 86 के सुदृढीकरण के लिए 22 करोड़ 65 लाख रूपए, दमोह हीरापुर एनएच 12 के लिए 9 करोड़ 11 लाख रूपए, सागर टोला से शहडोल राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 19 करोड़ 67 लाख रूपए, दिनारा-पचोर-चंदेरी-मुंगावली से मेलुआ चौराहे तक राष्ट्रीय राजमार्ग के सुदृढीकरण के लिए 18 करोड़ 19 लाख रूपए तथा सीधी-सिंगरौली हाईवे के लिए 529 करोड़ 40 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इसके साथ ही एनएच 26 पर टोल प्लाजा के निर्माण के लिए 9 करोड़ 42 लाख रूपए, भोपाल

शहर से गुजरने वाले एनएच 86 के सुदृढीकरण के लिए 6 करोड़ 61 लाख रूपए और बमीठा खजुराहो सड़क मार्ग के लिए 73 करोड़ 43 लाख रूपए की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है।

कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी जारी रहेगा उपार्जन कार्य

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू होने के दौरान भी प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर उपार्जन कार्य सतत चालू रहेगा। किसानों के हित में यह निर्णय लिया गया है कि उपार्जन कार्य को कोरोना कर्फ्यू के कारण बाधित नहीं होने दिया जाएगा। किसान भाई प्राप्त मैसेज के अनुसार निर्धारित तिथि को अपनी फसल विक्रय के लिये उपार्जन केंद्रों पर पहुँचें।

मंत्री श्री पटेल ने किया उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण

भोपाल। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने रविवार को हरदा जिले के छिपानेर में उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया। मंत्री श्री पटेल ने छिपानेर में गेहूँ एवं चना उपार्जन के संबंध में संबंधित जिला अधिकारियों की बैठक लेकर पुख्ता बंदोबस्त करने के निर्देश दिए।

मंत्री श्री पटेल ने निर्देशित किया कि गत वर्ष स्थापित उपार्जन केंद्रों के अनुसार इस वर्ष अधिक संख्या में उपार्जन केन्द्र स्थापित किये जाएँ। मैपिंग इस प्रकार की जाए कि पंजीकृत किसानों को असुविधा नहीं हो। उन्होंने कहा कि जिन गाँवों के किसानों को खरीदी केंद्रों पर पहुँचने में अधिक दूरी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उन किसानों को उनकी सुविधानुसार पास के खरीदी केंद्रों में स्थानांतरित किया जाए। श्री पटेल ने कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है और अन्नदाता को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। उपार्जन केंद्र पर पर्याप्त व्यवस्थाएँ की जायें, सभी मौलिक आवश्यकताओं जैसे पीने का शुद्ध एवं शीतल जल, शौचालय, छाया हेतु टेंट आदि की पर्याप्त व्यवस्थाएँ होना चाहिए। सभी अधिकारी लगातार उपार्जन केन्द्रों का सतत निरीक्षण करते रहें एवं कृषकों की समस्याओं का निराकरण करते रहें।

गाँवों में नल से जल के लिए उज्जैन में हो रहे 300 करोड़ रूपए के कार्य

भोपाल। प्रदेश की पूरी ग्रामीण आबादी को शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था किए जाने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयास तेजी से जारी हैं। नल कनेक्शन से हर घर में पेयजल की आपूर्ति किए जाने के लिए पीएचई विभाग और जल निगम द्वारा जलसंरचनाओं की स्थापना एवं विस्तार के कार्य किए जा रहे हैं।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा उज्जैन संभाग में 365 जलप्रदाय योजनाओं का कार्य जारी है। जलप्रदाय योजनाओं की लागत 300 करोड़ 09 लाख 58 हजार रूपए है, जिनमें उज्जैन जिले की 78, देवास 68, शाजापुर 43, आगर-मालवा 28, रतलाम 84 मंदसौर 42 तथा नीमच की 22 जलसंरचनायें शामिल हैं। इन जिलों के विभिन्न ग्रामों में पूर्व से निर्मित पेयजल अधोसंरचनाओं को नये सिरे से तैयार कर रेट्रोफिटिंग के अन्तर्गत भी कार्य किये जा रहा है।

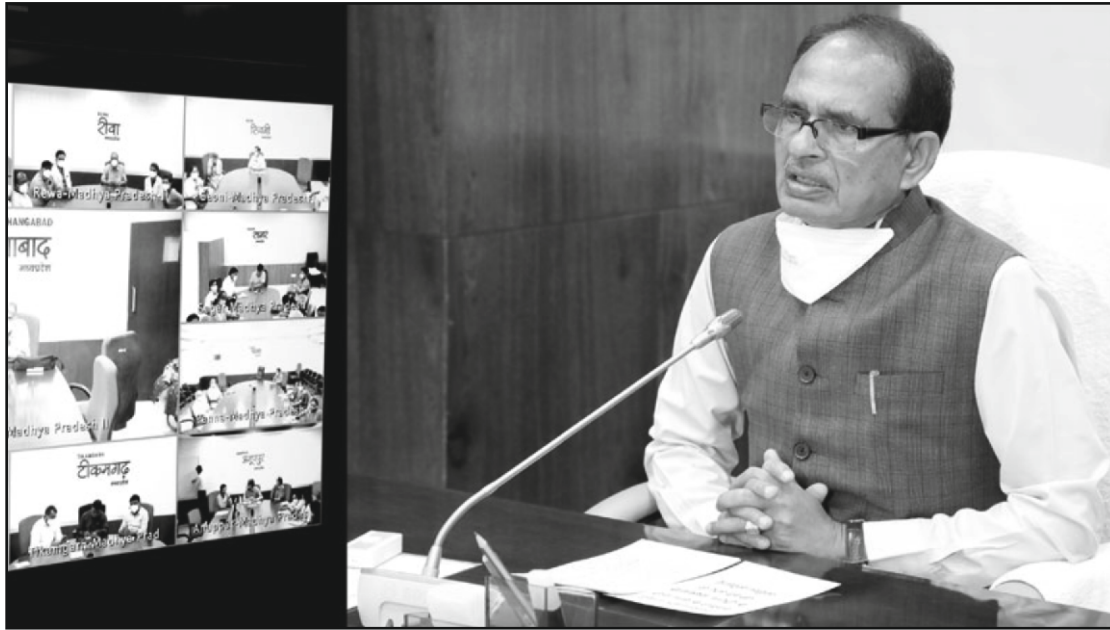
स्वास्थ्य कर्मी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचा रहे हैं : मुख्यमंत्री

कोरोना आपदा में धैर्य, संयम और आपसी सहयोग से होंगे विजयी • मुख्यमंत्री ने की नर्स, कम्पाउंडर, वार्डबॉय, आशा व आँगनवाड़ी कार्यकर्ता से चर्चा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना का संकट अभूतपूर्व है। स्थितियाँ पिछले साल से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। राज्य सरकार इलाज के लिए व्यवस्था करने, जन-जागरूकता फैलाने की दिशा में लगातार सक्रिय है, पर कोरोना के विरुद्ध असली लड़ाई नर्स, पैरा-मेडिकल स्टाफ, आशा कार्यकर्ता के माध्यम से ही लड़ी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रदेश के सभी जिलों के स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कर्मियों जैसे नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, कम्पाउंडर, वार्डबॉय, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी से जुड़े विशेषज्ञ, आशा कार्यकर्ता और आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मंत्रालय से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाने के महान काम में लगे हैं।

स्वास्थ्य कर्मी दो मोर्चों पर एकसाथ जुटे हैं

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अप्रैल माह कोरोना की दृष्टि से क्रिटिकल है। इसलिए इस समय सबसे ज्यादा धैर्य,



संयम और आत्म-विश्वास की जरूरत है। संक्रमण की चेन को तोड़ना और नए संक्रमण होने से रोकना यह हमारी प्राथमिकता है। राज्य सरकार अपनी तरफ से संसाधन जुटाने और इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। स्वास्थ्य कर्मी दोनों मोर्चों पर एक साथ कार्य कर रहे हैं पहला अस्पताल में कोरोना के मरीजों की टेस्टिंग ट्रीटमेंट और दूसरा 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों का टीकाकरण। कोरोना आपदा में धैर्य, संयम और आपसी सहयोग

से विजय प्राप्त की जायेगी।
शासकीय और निजी स्वास्थ्य क्षेत्र मिलकर करें चुनौती का सामना

अस्पतालों और बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है लेकिन उसकी भी अपनी सीमा है। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि संक्रमण की पहचान जल्द हो जाए ताकि मरीज की स्थिति गंभीर न हो और उन्हें अस्पताल जाना न पड़े। यदि होम आइसोलेशन में ही लोगों का संक्रमण ठीक होने लगेगा तो फिर

अस्पतालों पर बोझ अपने आप कम हो जाएगा। यह समय आपदा का है इसलिए सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र सबको मिलकर काम करना होगा। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की ताकत मिलकर ही इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकती हैं।

मरीजों के साथ मानवीय व्यवहार हो

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मरीज डॉक्टरों की सलाह, ट्रीटमेंट और दवाओं पर ही निर्भर रहता है। यदि वह अस्पताल तक

चल कर आया है तो निश्चय ही कोई गंभीर बात होगी। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि मरीज के साथ मानवीय व्यवहार हो, उन्हें दवाएँ और उपचार सही समय पर मिले उसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकना न पड़े। मरीजों को घंटों तक इलाज के लिए इंतजार न करना पड़े, बीमारी का गंभीरता के अनुरूप ही इलाज हो, आवश्यक दवाएँ ही लिखी जाये और अनावश्यक जाँच न कराई जाये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों का अस्पताल में परिवार के सदस्य साथ में नहीं होने से मनोबल गिरने लगता है। इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि मरीजों की निरंतर कॉउंसलिंग करते रहे और उनका हौसला बढ़ाएं। यह सकारात्मक कार्य आपने पहले भी किया है और आगे भी पूरे धैर्य और संयम के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह करेंगे, मुझे यह विश्वास है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पिछले एक साल में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कर्मियों ने मानव सेवा की जो मिसाल प्रस्तुत की है, वह अकल्पनीय है। प्रदेश की जनता इस त्याग और सहयोग को सदैव याद रखेगी।

ग्रामीण आजीविका मिशन 37 लाख ग्रामीण महिलाओं को कोरोना की रोकथाम हेतु कर रहा है प्रशिक्षित

भोपाल। भारत सरकार एवं राज्य शासन की मंशानुसार कोविड-19 महामारी के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार की रोकथाम हेतु कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार, स्वास्थ्य व्यवहार, प्रतिरक्षा निर्माण एवं टीकाकरण पर एनआरएलएम अंतर्गत गठित समस्त स्व-सहायता समूह सदस्यों को प्रशिक्षित एवं जागरूक करने का कार्य म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किया जा रहा है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन श्री एल.एम. बेलवाल ने बताया कि राज्य इकाई कार्यालय के संबंधित योजना प्रभारी को 8 अप्रैल 2021 एवं प्रत्येक जिले से 2 तथा प्रत्येक विकासखंड से 2 मास्टर ट्रेनर (कुल 732) का ऑनलाइन प्रशिक्षण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नई दिल्ली द्वारा 12 अप्रैल 2021 को दिया गया है। प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर 2 चरणों में आगामी प्रशिक्षण देंगे।

समस्त स्व-सहायता समूह सदस्यों को उनके ग्राम स्तर पर प्रशिक्षित करने के लिए प्रत्येक

गाँव से एक सीआरपी को ऑनलाइन प्रशिक्षित किया गया है। जिन गाँव में सीआरपी उपलब्ध नहीं हैं वहाँ ग्राम संगठन के पदाधिकारी अथवा सक्रिय स्व-सहायता समूह सदस्यों तथा समस्त सीएलएफ के पदाधिकारी, ऑफिस वियर्स तथा सीएलएफ एवं वीओ के सामाजिक गतिविधि उप-समिति के समस्त सदस्यों को ऑनलाइन प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस प्रकार लगभग 1 लाख 40 हजार सदस्यों का प्रशिक्षण प्रचलन में है।

द्वितीय चरण में प्रशिक्षित सीआरपी/वीओ के पदाधिकारी /समूह की सक्रिय सदस्य अथवा सीएलएफ पदाधिकारी के माध्यम से ग्राम के समस्त स्व-सहायता समूह सदस्यों को छोटे-छोटे समूहों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भौतिक रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है।

उपरोक्त प्रशिक्षण में समस्त प्रशिक्षणार्थियों को कोविड-19 टीकाकरण पर जागरूकता, कोविड-19 उचित व्यवहार, उपयुक्त स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा वर्धन, भारत सरकार की स्वास्थ्य

बीमा एवं स्वास्थ्य वित्त पोषित योजनाएँ, संक्रमण संचार एवं इसकी रोकथाम और रोग-प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपाय आदि विषय पर प्रशिक्षित किया जा रहा है।

उपरोक्त प्रशिक्षण से म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कुल प्रवेष्टित 44 हजार 553 ग्रामों में गठित 3 लाख 26 हजार 447 स्व-सहायता समूहों की लगभग 37 लाख महिला सदस्यों को कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में जागरूक एवं प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि 20 अप्रैल 2021 तक पूर्ण किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिये तैयार प्रशिक्षण सामग्री यथा मॉड्यूल, पोस्टर, हैण्डआउट, फ्लायर आदि मास्टर ट्रेनर्स एवं अन्य प्रशिक्षकों (समुदाय सदस्यों) को उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु

1.टीकाकरण :- कोविड-19 का टीका सुरक्षित है, यह हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरा है। कोविड-19 का टीका 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों के लिए। पंजीकरण

फोन पर, टीकाकरण केन्द्र पर स्वयं जाकर कराया जा सकता है। पात्रता प्रमाणित करने वाले दस्तावेज - फोटो आईडी (आधारकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पेनकार्ड, मनरेगा जाँव कार्ड आदि। सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों पर नि:शुल्क टीकाकरण के लिये दिन एवं स्थान स्वयं चुन सकते हैं।

2. कोविड 19 से बचने के उपाय (पंच सूत्र) :-

घर से बाहर निकलते समय और काम पर जाने के दौरान अपने मुँह और नाक को मास्क, दुपट्टे या साफ कपड़े से ढक कर रखें।

मुख्यमंत्री राहत कोष से जिलों को 52 करोड़ रुपये जारी

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिये प्रत्येक जिले को एक करोड़ रुपये की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से जारी की है। प्रदेश के 52 जिलों के लिये जारी की गई 52 करोड़ रुपये की राशि कोविड-19 के लिये आवश्यक उपकरणों के क्रय, पुनर्वास शिविरों में भोजन एवं कपड़े की व्यवस्था, मेडिकल शिविरों के संचालन, शिविरों का पर्यवेक्षण-संचालन, आवश्यक कार्यों में तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये क्रय की जाने वाली सामग्री और साफ-सफाई आदि पर व्यय की जा सकेगी।

प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री श्री मनीष रस्तोगी ने उक्त आशय का आदेश जारी कर प्रदेश के सभी 52 जिलों को राशि जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष से उपलब्ध करवाई गई राशि के व्यय के संबंध में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक अंतर्विभागीय समिति का गठन किया जायेगा। यह समिति कोविड-19 की रोकथाम के लिये किये गये व्यय का परीक्षण, पर्यवेक्षण एवं स्वीकृति के लिये सक्षम होगी।

एक मीटर की दूरी बनाये रखें, गले न लगाये और न ही हाथ मिलाएँ।

कम से कम 20 सेकण्ड के लिए अपने हाथ बार-बार धोएँ। सार्वजनिक स्थान पर थूके नहीं। अपनी आँख, नाक एवं मुँह को न छुएँ।

गर्म पानी पीएँ। पौष्टिक खाना खाएँ। अपने भोजन में अदरक, हल्दी, तुलसी, जीरा, दालचीनी शामिल करें।

यदि बुखार, सूखी खाँसी और साँस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण दिखते हैं तो चिकित्सा सहायता लें।

निर्धन उपभोक्ताओं को तीन माह का राशन मुफ्त दिया जाएगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा जिलों के कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संवाद

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शहरों और कस्बों के साथ ही प्रदेश के ग्रामों में भी संक्रमण बढ़ने से रोकना है। ग्रामों में जो सुरक्षित हैं, वे सुरक्षित रहें और बाहर न निकलें। जहाँ अधिक संक्रमित रोगी हैं वहाँ कन्टेनमेंट जोन बनाकर संक्रमण नियंत्रण सुनिश्चित करें। हर स्थिति में संक्रमण की चेन तोड़ना है। रहवासी संघ और स्वैच्छिक संगठन सहयोग करें ताकि जो व्यवस्थाएँ छोटी पड़ रही हैं, उन्हें पर्याप्त बनाया जा सके। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा कलेक्टर से संवाद किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खंडवा, बुरहानपुर प्रशासन के संक्रमण नियंत्रण के प्रयासों को सराहनीय बताया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी पात्र निर्धन उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों से एक साथ तीन माह का राशन निःशुल्क मिलेगा।

साँस की डोर न टूटे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में संक्रमित रोगियों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए गए हैं। रेमडेसिविर



इंजेक्शन भी लगातार आ रहे हैं। इनका न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी रोगी की साँस की डोर न टूटे।

हर व्यक्ति शंका होने पर टेस्ट अवश्य कराएँ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आइसोलेशन से जुड़ी पूरी व्यवस्थाएँ जिलों में सुनिश्चित करें। जिन व्यक्तियों को सर्दी-खाँसी, बुखार है, वे तत्काल जाँच करवाएँ, जाँच की रिपोर्ट आने तक स्वयं को आइसोलेशन

में रखें। संपल देने के बाद बहुत से लोग घूमते रहते हैं। इस पर भी नियंत्रण करना है। इससे परिवार को संक्रमित होने से बचाया जा सकेगा। यदि घर छोटा है तो कोविड केयर सेंटर जाकर व्यवस्था का लाभ लेना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कलेक्टर से कहा कि जिन जिलों में ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए गए हैं, वे प्लांट स्थापना का कार्य प्रारंभ करें। कुछ जिलों में ऑक्सीजन सिलेंडर लेने की पहल सराहनीय है। कलेक्टर द्वारा

स्थानीय प्रबंध भी सुनिश्चित हों।

भारत और मध्यप्रदेश हमारी माँ है

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आगामी 30 अप्रैल तक घर से न निकलें, संक्रमण की चेन तोड़ें। भारत और मध्यप्रदेश हम सबकी माँ है, इसके दूध की लाज रखना है। समाज, इस संकट में साथ खड़ा हो। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर से कहा कि आइसोलेशन केन्द्रों के लिए निजी और सरकारी भवन का उपयोग करें। कलेक्टर अपने स्तर पर नवाचार भी करें। हम

सम्मिलित प्रयासों से जंग जीत जायेंगे।

कारावास जाएंगे

कालाबाजारी करने वाले

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि औषधियों की कालाबाजारी करने वाले को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएसए) में कारावास भेजें। इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता लोगों का जीवन बचाना है। जीवनरक्षक इंजेक्शन को अधिक कीमत पर बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

वित्तीय समस्या नहीं होगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा किए जाने वाले स्थानीय प्रबंध में वित्तीय समस्या नहीं आने दी जाएगी। राज्य शासन स्तर से धन राशि की कमी नहीं होगी। यह प्रत्येक जिले का टास्क होना चाहिए कि कम से कम रोगी अस्पताल पहुँचें। होम आइसोलेशन व्यवस्था का अधिकतम प्रयास हो। इन्दौर में की गई पहल प्रशंसनीय है। सांसद, विधायक भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। सामाजिक संगठन सरकार के प्रयासों को मजबूत करें। निश्चित ही इस महामारी को हम सभी मिलकर हरा देंगे।

सेना भी करेगी संक्रमण नियंत्रण और रोगियों की देखभाल में सहयोग

मुख्यमंत्री श्री चौहान से मिले वरिष्ठ सैन्य अधिकारी • केंद्रीय रक्षा मंत्री से हुई मुख्यमंत्री श्री चौहान की चर्चा

भोपाल। देशभर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में भारतीय सेना भी हमकदम बनेगी। मध्यप्रदेश से हुई पहल के अंतर्गत आज मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने भेंट की। भेंट करने वालों में सुदर्शन चक्र कोर कमांडर श्री अतुल्य सोलंकी और ब्रिगेडियर आशुतोष शुक्ला शामिल हैं।

भोपाल, जबलपुर, सागर और ग्वालियर में होगी व्यवस्था

सैन्य अधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को बताया कि कोरोना संक्रमित रोगियों को सेना के अस्पतालों और आइसोलेशन केंद्रों में स्थान दिया जाएगा। भोपाल में लगभग 150, जबलपुर में 100, सागर में 40 और ग्वालियर में 40 आइसोलेशन बेड की व्यवस्था के लिए प्रयास आज से प्रारंभ किए जा रहे हैं।

रक्षा मंत्री से भी चर्चा हुई

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज ही केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ



सिंह से भी सेना से सहयोग के प्राप्त करने के संबंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा आवश्यकता हुई तो सेना द्वारा संचालित इन आइसोलेशन केन्द्रों में मध्यप्रदेश शासन आइसोलेटेड रोगियों के लिए ऑक्सीजन व्यवस्था भी उपलब्ध करवाएगा।

भोपाल स्थित आइसोलेशन केंद्र के लिए ऑक्सीजन लाइन भी स्थापित की जा सकती है। इससे गंभीर स्थिति होने पर आइसोलेटेड रोगी को आवश्यक उपचार मिल सकेगा।

पैरामेडिकल स्टाफ भी देंगे सेना के अधिकारियों ने

रोगियों की समुचित देखभाल के लिए पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराने के लिए भी आश्वस्त किया। कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए सेना की ओर से प्रदेश में बिस्तर उपलब्ध करवाने एवं पूर्ण सहयोग के लिए आश्वस्त किया गया। संक्रमण की बढ़ती

रफ्तार को देखते हुए आवश्यक प्रबंध हो जाने से आइसोलेशन रोगियों की देखरेख का कार्य हो सकेगा।

सेना पर गर्व है

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारतीय सेना पर हम सभी को गर्व है। संकट के समय में सेना से किए गए अनुरोध का अच्छा रिस्पांस मिला है। यह सच है कि प्रदेश में संक्रमण बढ़ा है। सरकारी प्रयासों का साथ जन-जागरूकता भी बढ़ रही है। आगामी 30 अप्रैल तक मध्यप्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू है। इसमें जनता भी सहयोग कर रही है।

वरिष्ठ अधिकारी अधिकृत

सेना द्वारा दिए जाने वाले इस सहयोग से संक्रमित रोगियों की बेहतर देखभाल की जा सकेगी। आवश्यक समन्वय के लिए मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी और सेना सुदर्शन चक्र भोपाल की ओर से ब्रिगेडियर आशुतोष शुक्ला अधिकृत किए गए हैं।

दीवार लेखन कर स्व-सहायता समूह की महिलाएं कर रही ग्रामीणों को जागरूक

भोपाल। "दो गज की दूरी-मास्क है जरूरी", साबुन से हाथ धोते रहें, साबुन नहीं तो सेनेटाइजर का उपयोग करते रहे। कोरोना से बचाव जरूरी है। लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। भीड़-भाड़ में नहीं जायें। भीड़ से बचें, बहुत इमरजेन्सी हो तभी मास्क लगाकर सुरक्षित घर से निकलें। यह जागरूकता का कार्य साईं कृपा स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा दीवार लेखन कर बखूबी समझाइश देकर लिखा जा रहा है।

मुरैना जिले के पहाड़गढ़ विकासखण्ड के साईं कृपा स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिये दीवार लेखन का कार्य बड़ी तीव्र गति से किया जा रहा है। दीवार लेखन कार्य में उनके द्वारा "दो गज की दूरी-मास्क है जरूरी" संदेश लोगों तक पहुंच रहा है। लोग कोरोना से बचने के लिये जागरूक भी हो रहे हैं।

स्व-सहायता समूह पहाड़गढ़ की अध्यक्ष श्रीमती आराधना सिंह धाकड़ ने बताया कि मध्यप्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मार्गदर्शन में 2018 में समूह का गठन किया गया था। समूह में 10



महिलाएँ हैं। समूह की महिलाओं को मध्यप्रदेश आजीविका मिशन के मार्गदर्शन में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड से बचने के लिये दीवार लेखन का कार्य, मास्क, सेनेटाइजर का कार्य सौंपा गया है, जिसे समूह की महिलाओं ने गंभीरता से लेते हुए पूरी ग्राम पंचायत में नारे लिखने का कार्य हाथ में लिया।

कोरोना के प्रति सजग रहने और जन-जाग्रति के लिये समूह की महिलाएँ घरों की दीवारों पर सावधानियाँ बरतने संबंधी स्लोगन लेखन कार्य कर रही हैं। साथ ही हर घर में मास्क लगाने और हाथ धोने के साथ ही अन्य लोगों से दूरी बनाये रखने की सलाह भी दी जा रही है। ग्रामीणों को कोविड टीकाकरण के लिये प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। इस कार्य में इस कार्य में समूह की सदस्य अनीता धाकड़, सुनीता

धाकड़, रामस्वरूपी धाकड़, सुरक्षा धाकड़, नारायण सिंह धाकड़ द्वारा सक्रिय भागीदारी निभाई जा रही है। समूह के प्रयासों से ग्रामीण भी कोरोना के प्रति सावधानी बरत रहे हैं। मध्यप्रदेश जन-अभियान परिषद कैलारस के सामाजिक कार्यकर्ता श्री सौरभ गौड़ एक युवा उद्यमी भी हैं। उनके द्वारा अपने क्षेत्र में कोरोना काल में राशन बांटने से लेकर मास्क वितरण एवं जागरूकता के लिये निरंतर कार्य किया जा रहा है। नागरिकों को कोरोना से बचाव के लिये सेनेटाइजर एवं कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक बनाकर कोरोना बीमारी से बचाने के सार्थक प्रयास कर रहे हैं। लोगों से सीधा संवाद कर उन्हें कोरोना के प्रति जागरूक रहने की शिक्षा देते हुए पीड़ितों को काढ़ा बनाने सहित कोरोना से बचाव की अन्य सावधानियाँ भी बताई जा रही हैं।

(पृष्ठ 1 का शेष)

प्रदेश में लघु, कुटीर और मध्यम....

50 हजार से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। प्रदेश में 1891 इकाइयाँ वर्चुअली आरंभ की जा रही हैं। इनमें 4227 करोड़ का निवेश हुआ है। यह इकाइयाँ 50 हजार से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में 572 इकाइयाँ मार्च 2021 तक स्थापित हो चुकी हैं। अगले तीन माह में 296 और अगले छह माह में एक हजार 23 इकाइयाँ स्थापित होंगी।

औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से प्रदेश में विकास के नए रास्ते खुलेंगे

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सकलेचा ने कहा कि उद्योग क्षेत्र में बहुत तेजी से तकनीकी बदलाव आ रहा है। वैश्विक स्तर की माँग के अनुसार प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को कदम से कदम मिलाकर चलने में सक्षम बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान के मार्गदर्शन में प्रदेश में आवश्यक व्यवस्थाएँ की जा रही

हैं। खजुराहो सांसद तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री व्ही.डी. शर्मा ने कहा कि प्रदेश में इतने व्यापक स्तर पर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से प्रदेश में विकास के नए रास्ते खुलेंगे।

मुख्यमंत्री ने किया उत्कृष्ट एम.एस.एम.ई. इकाइयों और स्टार्टअप संचालकों का सम्मान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश की उत्कृष्ट एम.एस.एम.ई. इकाइयों और स्टार्टअप संचालकों का सम्मान किया। कोरोना काल में पीपीई किट और फेस मास्क निर्माण में अभूतपूर्व कार्य के लिए मोहिनी हेल्थ एण्ड हाईजीन लिमिटेड पीथमपुर धार के श्री अवनीश बंसल, रक्षा उपकरण उत्पादन में लगे डी.के. इंसूलेशन इण्डस्ट्रीज भोपाल के श्री डी.के. कोहली का सम्मान किया गया। गुगल वेंचर्स, सैमसंग और बायजूस जैसी संस्थाओं को मांग आधारित टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ उपलब्ध कराने वाले स्टार्टअप इंजीनियर बाबू आईटी सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड इंदौर की सुश्री अदिति चौरसिया, मध्य भारत के

सबसे बड़े तथा एकमात्र कार्बन न्यूट्रल हाइपर स्केल डाटा सेंटर रैंक बैंक डाटा सेण्टर्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर के श्री नरेन्द्र जैन और प्रदेश की एकमात्र ऑनलाइन शेड्यूलिंग कम्पनी एपॉइण्टी इंडिया भोपाल के श्री निमेष सिंह का भी सम्मान किया गया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की उद्यमियों से बातचीत

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के उद्यमियों से वर्चुअली संवाद भी किया। नीमच में हनी और हर्बल प्रोडक्ट्स पर केन्द्रित दीर्घायु भवः हनी एण्ड हर्बल इकाई की श्रीमती मीनाक्षी मालव, खरगोन में पी.पी. बैग निर्माण इकाई के संचालक श्री प्रवीण गुप्ता, बालाघाट में सीड लाख उत्पादन इकाई चलाने वाले श्री महेन्द्रा परधी, सतना में पास्ता और ब्रेड निर्माण इकाई संचालक श्रीमती मुस्कान रावलानी और टीकमगढ़ में आजाद स्टील फर्नीचर के मालिक श्री मोहम्मद शहजाद मंसूरी से बातचीत की। संचालक एम.एस.एम.ई श्री भास्कर लाक्षाकार ने आभार माना।

शासकीय विद्यालयों में 13 जून तक रहेगा ग्रीष्मकालीन अवकाश : राज्यमंत्री

अशासकीय विद्यालयों में 30 अप्रैल तक नहीं होगा कक्षाओं का संचालन

सभी शासकीय एवं अशासकीय छात्रावासों को किया गया बंद

भोपाल। स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने बताया कि प्रदेश में कक्षा पहली से आठवीं तक के शासकीय एवं अनुदान प्राप्त समस्त विद्यालयों के लिए 15 अप्रैल से 13 जून 2021 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। इसके साथ ही अशासकीय विद्यालयों में कक्षा पहली से आठवीं तक की कक्षाओं का भौतिक संचालन 30 अप्रैल 2021 तक नहीं किया जाएगा। इन कक्षाओं का ऑनलाइन शिक्षण कार्य जारी रह सकेगा। श्री परमार ने बताया कि प्रदेश में सभी शासकीय एवं अशासकीय छात्रावासों को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। श्री परमार ने कहा कि वर्तमान कोरोना महामारी की परिस्थिति और विद्यालयीन छात्रों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध सभी जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक एवं प्राचार्य को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कक्षा पहली से आठवीं तक की शालाओं में कार्यरत सभी शासकीय शिक्षक ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बोर्ड परीक्षाओं के पूर्ण होने तक मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। बोर्ड परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षण या अन्य शासकीय कार्य के लिए ड्यूटी लगाए जाने पर आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे। जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि बोर्ड परीक्षाएँ संबंधित बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा मंडल, सीबीएसई, आईसीएसई इत्यादि के निर्देश के अनुसार ही आयोजित होंगी।

(पृष्ठ 1 का शेष)

पहली बार, एनसीडीसी को डॉएच बैंक...

किसानों को स्थायी आजीविका हासिल करने में उनकी यात्रा को सहयोग देने हेतु प्रयासरत रहे हैं।

सहकारिताएं जर्मनी के लिए कोई नया विषय नहीं है तथापि, आज जर्मनी के 7,500 सहकारी उद्यमों में 20 मिलियन से भी अधिक सदस्य हैं। इसकी तुलना में संख्या विश्व में शीर्ष रैंकिंग पर है। लगभग 94: भारतीय किसान कम से कम एक सहकारिता के सदस्य हैं। भारत सरकार की आधुनिक कृषि पहलें सहकारिताओं को जमीनी स्तर से परिवर्तित कर रही हैं।

भारत में डॉएच बैंक द्वारा की गई पहल, गत वर्षों में भारत में जर्मन कंपनियों द्वारा दिखाये गये व्यवसाय अभिरुचियों में से एक है। वर्तमान में भारत में 1700 से अधिक जर्मन कंपनियाँ सक्रिय हैं, जो लगभग 4,00,000 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से नौकरियाँ प्रदान करती हैं। यूरोप एवं भारत के मुख्य दस वैश्विक व्यापारिक भागीदारों में, जर्मनी भारत का सबसे शीर्ष व्यापारिक भागीदार है।

एनसीडीसी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक विकासात्मक एवं वित्त पोषण

संस्थान है। वर्ष 2014 से अब तक विभिन्न प्रकार की सहकारिताओं को 16 बिलियन यूरो ऋण प्रदान कर चुका है। शून्य शुद्ध एनपीए के साथ एनसीडीसी सभी राज्यों में अपने 18 क्षेत्रीय निदेशालयों के साथ अखिल भारतीय उपस्थिति दर्ज कर चुका है।

इसी प्रकार, डॉएच बैंक निगमों, सरकारों एवं अन्य को कॉर्पोरेट व बैंक लेन-देन, ऋण, केंद्रित निवेश बैंकिंग के साथ-साथ खुदरा एवं निजी बैंकिंग प्रदान करता है। गत 40 वर्षों में, डॉएच बैंक भारत के सबसे बड़े विदेशी बैंकों में से एक बन गया है, जिसकी देशभर के 16 शहरों में शाखाएँ हैं। शपारिया ने कहा कि बैंक ने समाज एवं लोगों की बेहतरी के लिए सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक जैसी विचारधारा वाले भागीदारों के साथ काम किया।

इस कार्यक्रम में आदित्य बागडी, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स कमेटी के सह-अध्यक्ष ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कृषि- व्यापार एवं खाद्य प्रसंस्करण विषय पर आईसीसी-एनसीडीसी समझौता ज्ञापन का विशेष ध्यान एफ.पी.ओ. द्वारा निर्यात संवर्धन पर केंद्रित होगा।

धान मिलिंग के लिए प्रदेश के बाहर के मिलर्स आमंत्रित

धान मिलिंग एवं निस्तारण के लिए गठित मंत्रि-मंडलीय उप समिति की बैठक संपन्न

भोपाल। खरीफ वर्ष 2020-21 के लिए धान उपार्जन एवं निस्तारण के लिए प्रदेश के बाहर के मिलर्स को आमंत्रित किया जाएगा। धान एवं निस्तारण के लिए गठित मंत्रि-मंडलीय उप समिति की बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि इस संबंध में शीघ्र ही विज्ञापन जारी कर मिलर्स को आमंत्रित किया जाएगा। समिति की बैठक में वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, कृषि मंत्री श्री कमल पटेल, सहकारिता मंत्री श्री अरविन्द भदौरिया एवं आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं जल-संसाधन राज्य मंत्री श्री रामकिशोर काँवरे ने वर्चुअली भाग लिया।

प्रोत्साहन राशि में की दोगुनी वृद्धि

खाद्य मंत्री श्री सिंह ने बताया कि विगत दिनों मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई चर्चा में मिलर्स द्वारा प्रोत्साहन राशि को 25 रुपये प्रति क्विंटल से



बढ़ाकर 50 रुपये किए जाने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा प्रोत्साहन राशि 50 रुपये प्रति क्विंटल कर दी। बाद में मिलर्स द्वारा धान के टूटन का हवाला देते हुए नुकसान के कारण मिलिंग में रुचि नहीं लेते हुए इसे 100 एवं 200 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने की माँग की है।

मंत्री श्री सिंह ने बताया कि अन्य राज्यों में मिलर्स को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में क्रमशः

उत्तर प्रदेश में 20 रुपये प्रति क्विंटल, छत्तीसगढ़ में अरवा और उष्णा चावल के लिए 20, 40 और 45 रुपये प्रति क्विंटल, आंध्र प्रदेश में सार्टेक्स चावल के लिए 60 एवं अच्छे चावल के लिए 50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

सहकारिता मंत्री श्री अरविन्द भदौरिया ने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में 100 एवं 200 रुपये की राशि व्यवहारिक रूप से बहुत अधिक है। उन्होंने कहा कि

मिलिंग के लिए अन्य राज्यों के मिलर्स को आमंत्रित किया जाना चाहिए। जहाँ तक टूटन का प्रश्न है टूटन अन्य राज्यों में भी होगी।

धान मिलर्स को प्रोत्साहित करने के लिए

राज्य शासन द्वारा समय-सीमा में धान उपार्जन के दौरान मिलिंग शुरू करने के लिए नीति बनाई गई, प्रोत्साहन राशि को दोगुना करने के साथ ही प्रतिभूति राशि 60 से 70 प्रतिशत की गई। मिलर्स द्वारा धान/चावल गोदाम

से मिल तक ले जाने एवं लाने के लिए परिवहन की दरें निर्धारित की गईं। धान की लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए दरें जारी की गईं। पूर्व में यह लोडिंग-अनलोडिंग का प्रावधान नहीं था। इसके अलावा मिलर्स को समय पर भुगतान किया जा सके, इसके लिए देयकों के ऑनलाइन बिलिंग का प्रावधान किया गया।

बैठक में कोरोना संक्रमण के कारण मिलर्स एसोसिएशन की ओर से सतना से ललित माहेश्वरी, बालाघाट से गंभीर संचेती, सिवनी से आशीष अग्रवाल, रीवा से दिलीप सिंह, जबलपुर से मुकेश जैन, कटनी से श्री करमचंद असरानी, दावत फूड से श्री राजेन्द्र वाधवान, रॉयल ग्रेन्स से श्री अब्दुल ताहिर, सागर से श्री क्षितिज मिश्र, श्री विज्ञान लढढा एवं श्री शंकर मेहानी ने वर्चुअली भाग लिया। संचालक खाद्य श्री तरुण पिथौड़े एवं प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम श्री अभिजीत अग्रवाल ने वर्चुअली भाग लिया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड-19 पर मुख्यमंत्रियों से किया संवाद

कोरोना आपदा का सामना करने के लिए देश को एकजुट होना होगा—मुख्यमंत्री श्री चौहान

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना की आपदा का सामना करने के लिए देश को एकजुट होना होगा। यह बड़ी विपदा है। ऑक्सीजन की कमी जैसी समस्याएँ सामने हैं, जिनकी कल्पना नहीं थी। लेकिन हम अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश भी एकजुट होकर खड़ा है। इस एकजुटता से ही जन-जन में आत्म-विश्वास बनेगा और हम संकट पर विजय पाएँगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि केन्द्र ने राज्यों को ऑक्सीजन आवंटित की है। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह से लगातार सहयोग मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ऑक्सीजन परिवहन को डिजिस्ट्र मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत सम्मिलित करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का आभार माना। उन्होंने कहा कि राज्यों को अपने स्तर पर भी ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए



प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आयोजित कोविड-19 पर मुख्यमंत्रियों से वर्चुअल संवाद में भाग ले रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग और लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी भी उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में 11 राज्यों के मुख्यमंत्री सम्मिलित हुए। नीति आयोग के सदस्य डॉ. बी.के. पाल ने देश में कोविड की स्थिति पर प्रस्तुतीकरण दिया। मध्यप्रदेश द्वारा ऑक्सीजन के मितव्ययी उपयोग के लिए किए गए प्रयासों की प्रस्तुतिकरण में सराहना हुई। ऑक्सीजन की व्यवस्था के

लिए निरंतर प्रयास जारी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश में ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं। इन्दौर से दो टैंकर वायुसेना के विमान द्वारा जामनगर भेजे जा रहे हैं। इससे सड़क परिवहन में लगने वाले समय को बचाया जा सकेगा। प्रदेश में ऑक्सीजन बचाने के उद्देश्य से ऑक्सीजन ऑडिट की व्यवस्था की गई है। सभी अस्पतालों को पोर्टल से जोड़ते हुए, ऑक्सीजन का मितव्ययी उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। इस व्यवस्था से खण्डवा में अनुकरणीय पहल सामने आयी है। जहाँ 80 सिलेंडर उपयोग में आते थे, जिनकी संख्या घटकर 25 हो गई है। बीना रिफाइनरी में

उपलब्ध ऑक्सीजन का उपयोग करने के लिए रिफाइनरी के पड़ोस में ही 1000 बिस्तर का अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है।

सर्दी, खाँसी, जुकाम के मरीजों के लिए सहायता केन्द्र

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारा प्रयास यह है कि लोग घर पर ही ठीक हों और उन्हें अस्पताल जाने की आवश्यकता न पड़े। इसके लिए होम आइसोलेशन व्यवस्था में रह रहे मरीजों को डॉक्टर दो बार टेलीफोन से संपर्क करते हैं। मध्यप्रदेश में कोविड सहायता केन्द्र आरंभ किए गए हैं। यहाँ सर्दी, खाँसी, जुकाम के मरीजों की जाँच होगी। उन्हें मेडिकल

किट उपलब्ध कराकर आइसोलेट किया जा रहा है। कोविड केयर सेंटरों की व्यवस्था को बेहतर बनाते हुए उन्हें अस्पताल के विकल्प के रूप में स्थापित किया जा रहा है।

रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग पर गाईड लाइन आवश्यक

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग के संबंध में भारत सरकार की ओर से निश्चित गाईड लाइन जारी होना आवश्यक है।

दवाइयों की कालाबाजारी पर रासुका

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इंजेक्शन सहित सभी महत्वपूर्ण दवाइयों की कालाबाजारी करने पर रासुका के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। अफवाह उड़ाने वालों और कृत्रिम कमी का माहौल बनाने वालों के विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए कर्फ्यू का प्रभावी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जानकारी दी कि मध्यप्रदेश में जनता ने स्वयं तय कर कोरोना कर्फ्यू क्रियान्वित किया है। गाँवों में जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए कर्फ्यू प्रभावी रहा है।

कोरोना संक्रमित रोगियों को ऑक्सीजन आपूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता

सभी जिलों में होगी सीटी स्कैन की व्यवस्था • मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप्स के सदस्यों से चर्चा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जब तक कोरोना पूरी तरह नियंत्रित नहीं होता, सरकार और समाज को मिलकर लड़ना होगा। जन सहयोग से ही इस संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। कई बार कमी की खबरों के संदर्भ में संग्रहण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। कालाबाजारी और संग्रहण पर कठोर कार्यवाई की जाएगी। वर्तमान में 180 लाख में टन उपलब्धता है। आज गुजरात के मुख्यमंत्री से भी मध्यप्रदेश के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए चर्चा की है। नब्बे प्रतिशत ऑक्सीजन अस्पतालों के लिए सुरक्षित कर दी गई है। उद्योगों को दस प्रतिशत ऑक्सीजन ही दी जायेगी। कोरोना संक्रमित रोगियों के लिए प्राथमिकता से आक्सीजन की व्यवस्था रहेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी जिलों में सीटी स्कैन की व्यवस्था जल्द से जल्द की जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा जिलों के क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप्स के सदस्यों से



चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना नियंत्रित करने के लिए तीन दिशाओं में कार्य किया जा रहा। जन-जागरूकता द्वारा फेस मास्क के उपयोग, उचित दूरी, बार-बार हाथ धोने जैसे व्यवहार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। दूसरा रोगी के बेहतर उपचार एवं देखभाल के लिए हर संभव व्यवस्था स्थापित की जा रही है। साथ ही प्रदेश में वेक्सीनेशन को गति दी जा रही है।

ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए कंट्रोल रूम गठित
राज्य में ऑक्सीजन व्यवस्था के लिए समीक्षा की जा रही है। एक नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है। श्री पी नरहरि को इसका प्रभारी बनाया गया है। प्रतिदिन मध्यप्रदेश के एमएसएमई सेक्टर द्वारा आक्सीजन उत्पादन के साथ

अन्य प्रांतों से आक्सीजन बुलवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

जनता का सहयोग जरूरी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक आयु वाले प्रत्येक व्यक्ति को वेक्सीन लगवाना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी नागरिक प्रदेश में जन-जागरण में सहयोग दें। आम नागरिकों द्वारा कोविड के दृष्टिगत अनुकूल व्यवहार की अपेक्षा है। आमजन से आग्रह है कि लोग घरों से अनावश्यक रूप से न निकले और संक्रमण रोकने में सहयोग करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मैं भी संक्रमण रोकने के लिए स्वास्थ्य आग्रह पर बैठा था। अनेक वालेंटियर्स इस कार्य में साथ दे रहे हैं। अस्पतालों में भी अनेक वारियर्स कठिन हालातों में जुटे हुए हैं।

इनका सम्मान किया जाएगा।

टीका उत्सव

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जयंती से 14 अप्रैल डॉ. अंबेडकर जयंती तक टीका उत्सव रहेगा। इसके लिए तैयारियाँ पूरी की जाएं। कोविड परिस्थितियों पर सब गंभीर रहे। जन-प्रतिनिधि जनता को मास्क के उपयोग की समझाइश दें। इस क्षेत्र में कार्य कर रहे वालेंटियर्स सक्रिय हैं। अनेक स्वैच्छिक संगठन भी कार्य कर रहे हैं।

6 जिलों में किल कोरोना-II अभियान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बैतूल, छिन्दवाड़ा, बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर और झाबुआ जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण अधिक फैल रहा है। यहाँ किल कोरोना-II अभियान शुरू

किया जायेगा। इसके अंतर्गत ग्राम स्तर पर सर्वे कर प्रभावित व्यक्तियों की जाँच और इलाज की व्यवस्था होगी।

सुविधाओं में निरंतर वृद्धि
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में बिस्तर क्षमता बढ़ाई जा रही है। प्रत्येक जिले में सीसीसी ज्यादा सक्षम बनाए जा रहे हैं। इस माह के अंत तक अधिक से अधिक एक लाख केस भी आ जाएं, उसके अनुरूप इंतजाम किये जा रहे हैं। करीब एक लाख इंजेक्शन की व्यवस्था कर आपूर्ति प्रारंभ हो चुकी है। भारत सरकार से अतिरिक्त वेंटिलेटर मिल रहे हैं। निजी अस्पतालों से अनुबंध कर रोगियों के लिए व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जा रही हैं।

अपर मुख्य सचिव श्री मोहम्मद सुलेमान ने प्रेजेंटेशन में बताया कि कल प्रदेश में करीब पाँच हजार केस आए हैं, जो चिंतनीय है। देश में करीब डेढ़ लाख केस आए हैं। कुल पॉजिटिव प्रकरण वाले 66 प्रतिशत रोगी आइसोलेशन व्यवस्था में हैं। प्रदेश में सक्रिय केस 32 हजार 707 हैं। जहाँ तक बेड ऑक्यूपेंसी की बात है, प्रदेश में कुल 34 प्रतिशत रोगी अस्पतालों में दाखिल हैं। प्रदेश में सामान्य बेड का 8 प्रतिशत रोगियों द्वारा उपयोग हो रहा है। ऑक्सीजन बेड 18 प्रतिशत और आईसीयू बेड 8 प्रतिशत ही उपयोग में आ रहे हैं।

प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिये युद्ध स्तर पर प्रयास जारी : मंत्री श्री भदौरिया

ऑक्सीजन की उपलब्धता एवं परिवहन की समीक्षा

भोपाल। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि कोरोना नियंत्रण एवं मरीजों के उपचार की व्यवस्थाएँ राज्य सरकार प्राथमिकता से कर रही है। गंभीर मरीजों को समय पर ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये सतत प्रयास जारी हैं। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र, गुजरात, झारखण्ड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य से सम्पर्क कर प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति के प्रयास किये गये हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये की कोरोना मरीजों का समुचित उपचार सुनिश्चित किया जाए।

मंत्री श्री भदौरिया आज म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कार्पोरेशन लिमिटेड के भवन में कोविड-19 के लिये स्थापित ऑक्सीजन



नियंत्रण कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे थे। बैठक में अपर मुख्य सचिव जल-संसाधन श्री एस.एन. मिश्रा, नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन श्री पी. नरहरि, संचालक तकनीकी शिक्षा एवं कौशल श्री पी. धनराजू और आयुक्त सह सचिव सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम

श्री विवेक पोरवाल मौजूद थे। बैठक में मध्यप्रदेश को अन्य राज्यों यथा महाराष्ट्र, गुजरात, झारखण्ड, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ राज्यों से ऑक्सीजन प्राप्त करने और ऑक्सीजन की उपलब्धता एवं उसके परिवहन की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। मंत्री श्री अरविंद सिंह

भदौरिया ने कहा कि संबंधित राज्यों में संबंधितों से चर्चा कर समस्या के शीघ्र निराकरण के प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं इस दिशा में निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में कोरोना के उपचार और जरूरी संसाधनों की आपूर्ति के लिये

स्थानीय प्रशासन जन-प्रतिनिधियों के साथ मिल कर बेहतर व्यवस्थाएँ बनाने में जुटे हैं, ताकि मरीजों को उचित इलाज मुहैया हो सके। मंत्री श्री भदौरिया ने बताया कि गैस टैंकर की व्यवस्था व उसके परिवहन के लिये केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान और केन्द्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल से चर्चा कर उक्त व्यवहारिक कठिनाईयों का शीघ्र निराकरण करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं। निश्चित ही सकारात्मक परिणाम शीघ्र सामने आयेंगे। नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन श्री पी. नरहरि ने बताया कि विभाग द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है, जिस पर हर घंटे अपडेट जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही कंट्रोल रूम भी 24 घंटे काम कर रहा है।